

# अनुगामिनी

मुकेश सहनी ने कहा, झुकूंगा नहीं 3 | सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को हस्तांतरित किए 8

## शिक्षा के विकास में शिक्षिकों की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री लेप्चा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 24 मार्च । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित छठे राज्य शिक्षक एड्युकेटर सम्मेलन 2021-22 का उद्घाटन आज शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा ने किया। इसका आयोजन गंगटोक में एससीईआरटी के सभागार में किया गया। मंत्री के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा जीपी उपाध्याय और सलाहकार शिक्षा एमपी सुब्बा, शिक्षा विभाग के निदेशक और अन्य गणनायन व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और शिक्षक उपस्थित रहे।

निदेशक, एससीईआरटी, डॉ. राबिन छेत्री ने दो दिवसीय सम्मेलन में सभी गणनायन व्यक्तियों और मेहमानों का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि सम्मेलन अद्वितीय है व्यांकिंग सिक्किम देश का एकमात्र राज्य है जहां शिक्षक एड्युकेटरों की बैठक होती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का सम्मेलन

मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री

एससीईआरटी के लिए विशेष है क्योंकि यह पहली बार है कि यह आयोजन एक समर्पित-एससीईआरटी भवन में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में निरंतर समर्थन देने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

अपने मुख्य भाषण में अपर मुख्य सचिव शिक्षा जीपी उपाध्याय ने सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी और राज्य में एक प्रधानी और कुशल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में एससीईआरटी की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनईपी के मूल तत्वों पर अपने विचार व्यक्त किए, जो पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर एक मजबूत नींव बनाने, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री



कुंगा नीमा लेप्चा ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के नेतृत्व में एससीईआरटी की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनईपी के मूल तत्वों पर अपने विचार व्यक्त किए, जो पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर एक मजबूत नींव बनाने, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

मंत्री लेप्चा ने कहा कि

शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे छात्रों को सीखने के लिए अधिक जिम्मेदारी ग्रहण करें और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में सक्षम बनाएं ताकि उन्हें पाठ्यपुस्तकों के विकास में शामिल करने के लिए अधिकारी और बाहर कई तरह के रास्ते तलाशें का अवसर प्राप्त करें। उन्होंने शिक्षण समूदाय से एनईपी 2020 की छवत्रिया में एक संग्रह और जैविक कृषि पुस्तक का विवेचन भी किया गया। उद्घाटन सत्र का समापन संयुक्त निदेशक, एससीईआरटी, डॉ. शांति राम अधिकारी द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

कार्यक्रम को सलाहकार शिक्षा एमपी सुब्बा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर, एससीईआरटी ने प्राथमिक स्तर के लिए नई पाठ्यपुस्तकों के विकास में शामिल करने के लिए एक वैज्ञानिक दल के विकास में प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखने की अपील की।



अनुगामिनी का.सं.

नामची, 24 मार्च । प्रशिक्षम बीमारी (एससीईएस) अधिनियम, 2021 में विभिन्न कमियों की ओर इशारा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी, मजदूर मोर्चा की टीम ने अप्राप्ति विभाग की संयुक्त आयुक्त श्रीमती टीडीब्ल्यू. शेरपा से मुलाकात की और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।

मोर्चा अध्यक्ष किनते ग्याल्छेन भूटिया और कार्यकारी अध्यक्ष हरि छेत्री के नेतृत्व में मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि नए अधिनियम में इन्हें बरकरार रखा जाए।

दूसरी ओर, भाजपा ने विभाग से मांग की है कि वह पुराने सिक्किम वेज कोड के प्रावधानों में संशोधन करे, जो कि अप्राप्ति विभाग की संयुक्त आयुक्त की ओर इशारा करता है। इस प्रकार करवा एक वेज कोड के लिए निर्माण करने के बारे में सकारात्मक आश्वासन दिया था और आश्वासन दिया था कि गैर-प्राथमिक के उन मुद्दों को संशोधन के माध्यम से फिर से शामिल किया जाएगा। उन्होंने यूटीएमएफ को आश्वासन दिया कि वह पुराने प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों को अधिकारिक रूप से लागू नहीं किया जाता है।

बैठक के दौरान भाजपा कार्यकारी मोर्चा ने एनएचीपी स्टेज-4 पर कर्मचारियों को हो रही परिवहन समस्या की भी विभाग से शिकायत की है। यह कहते हुए कि परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को काम पर जाने के लिए 16 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है, कंपनी पक्ष ने अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है और इस संबंध में विभागीय हस्तक्षेप की मांग की है।

इस दौरान डीसी-पाकिम ने एनएचआईडीसीएल द्वारा निर्मित

अधियंता, डीएफओ टी (नामची), एडीएफओ (कालिम्पॉग फारिस्ट डिवीजन), बीडीओ सुब्बुक, आपदा प्रबंधन डीपीओ (नामची) के अलावा डीई (एनएच डिवीजन), एडी ट्रॉफिज (नामची) तथा पुलिस, पंचायतों के अलावा अय्य विभागों के अधिकारी शामिल रहे।

दल के सदस्यों ने मल्ली पीचर्सी (सिक्किम साइड), भालुखोला (प्रशिक्षम बंगल साइड) तथा त्रिवेणी (सिक्किम) का भी दौरा कर परिवर्षिति का जायाना लिया। यह स्थान परिषम बंगल के लेबरबोरों के विपरीत अविस्थित है। इस दौरान आगामी मानसून के दिनों में इलाका में होने वाली सम्भावित क्षति के रोकथाम हेतु दीवारीविधि उपायों पर चर्चा की गयी।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

प्रिसिपल चीफ कंसलटेंट डॉ. सार्की भूटिया, जिला नोडल सह सर्विलास अधिकारी डॉ. जुनिता यो-ञन, डीआरसीएचओ डॉ. प्रतीक साइली (एमओटीसी), डॉ. अंजू राई (डीटीओ), ट्रीबी चैम्पियन एन-जीओ के विर्खा राई एवं अन्य गणनाय अधिकारी टीडीबी लडाई हुई।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

खतरनाक बीमारी की चेपट में आकर अपना जीवन गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इससे पीड़ित होते हैं।

कार्यक्रम के दौरान डीटीओ डॉ. अंजू राई ने बताया कि 2025 तक देश से ट्रीबी का समूल उम्मूलन सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा, इसके लिए सरकार रेपिड मॉलिलियूल टेस्ट एवं अन्य कदमों द्वारा इसकी नियुक्ति करने को प्रतिवधि है।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

प्रिसिपल चीफ कंसलटेंट डॉ. सार्की भूटिया, जिला नोडल सह सर्विलास अधिकारी डॉ. जुनिता यो-ञन, डीआरसीएचओ डॉ. प्रतीक साइली (एमओटीसी), डॉ. अंजू राई (डीटीओ), ट्रीबी चैम्पियन एन-जीओ के विर्खा राई एवं अन्य गणनाय अधिकारी टीडीबी लडाई हुई।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

खतरनाक बीमारी की चेपट में आकर अपना जीवन गंवाते हैं और करीब 28,000 लोग इससे पीड़ित होते हैं।

कार्यक्रम के दौरान डीटीओ डॉ. अंजू राई ने बताया कि 2025 तक देश से ट्रीबी का समूल उम्मूलन सरकार की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा, इसके लिए सरकार रेपिड मॉलिलियूल टेस्ट एवं अन्य कदमों द्वारा इसकी नियुक्ति करने को प्रतिवधि है।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

प्रिसिपल चीफ कंसलटेंट डॉ. सार्की भूटिया, जिला नोडल सह सर्विलास अधिकारी डॉ. जुनिता यो-ञन, डीआरसीएचओ डॉ. प्रतीक साइली (एमओटीसी), डॉ. अंजू राई (डीटीओ), ट्रीबी चैम्पियन एन-जीओ के विर्खा राई एवं अन्य गणनाय अधिकारी टीडीबी लडाई हुई।

अपने वर्कशैर में श्रीमती रामचंद्री

शामिल हो गयी।

प्रिसिपल चीफ कंसलटेंट डॉ. सार्की भूटिया, जिला नोडल सह सर्विलास अधिकारी डॉ. जुनिता यो-ञन, डीआरसीएचओ डॉ. प्रतीक साइली (एमओटीसी), डॉ. अंजू राई (डीटीओ), ट्रीबी चैम्पियन एन-

## अदाणी फाउंडेशन का पोषण वाटिका पर छः दिवसीय प्रशिक्षण, कुपोषण दूर करने पर जोर

गणेश सिंह 'विशाल'

सिंगराली, 24 मार्च । सरई तहसील अंतर्गत बासी बेरदहा गांव में पोषण संबंधी जागरूकता अभियान के तहत अदाणी फाउंडेशन द्वारा पोषण वाटिका व सभी उत्पादन पर छः दिवसीय मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का ड्रेश्य सीमित संसाधन में घेरेतु स्तर पर सालों भर ताजी सञ्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना और बाजार से सञ्जियों की खरीद पर होने वाले खर्च को कम करना है। पिछले गुरुवार से मंगलवार तक आयोजित इस कार्यक्रम में बासी बेरदहा गांव के कुल 19 महिलाएं और 12 पुरुषों को उनके खेतों में ले जाकर महिला उद्यमी बहुदेशी सहकारी समिति की श्रीमती सावित्री आर्मे और अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेप्टर की श्रीमती प्रियंका सिंह के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त अदाणी फाउंडेशन के तरफ से सभी 31 लाभार्थी ग्रामीणों के बीच निःशुल्क पोषण वाटिका किट प्रदान किया गया जिसमें उत्तर किस्म के पालक, भिड़ी, लोबिया, केरला, लोकी, लाल साग और मिर्च के बीज थे।

अदाणी फाउंडेशन के तरफ से प्रशिक्षकों ने लाभार्थी ग्रामीणों को बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य किस्मों से अधिक होती है, जिससे कि सञ्जियों एवं फसलों में पोषक तत्व की मात्रा को सस्ते एवं सरल तरीके से बढ़ावा जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान जलवायन अनुकूल फसल प्राणीता द्वारा पोषण प्रबंधन के साथ-साथ यह भी बताया गया कि कैसे जैविक खेती अपनाकर और जीवाणु खद का उत्तरांग पोषण वाटिका में करके पौष्टिक सब्जी उत्पाद जासकता है। इस प्रशिक्षण में इस बात का भरोसा दिया गया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने और सीमित संसाधन होने के बावजूद भी सभी लोग कुपोषण से प्रभावशाली तरीके से लड़ सकते हैं और यह पोषण वाटिका का निर्माण और मौसमी सब्जी के पौधों को लाग कर किया जा सकता है। खास बात यह है कि पोषण वाटिका के लिए जमीन के किसी बड़े हिस्से की जरूरत नहीं है और इसका निर्माण आप अपने घरों के आगे या पीछे के छोटे हिस्से में भी कर सकते हैं। बागवानी के लिए वाटिका लगाने और सब्जी उत्पादन जैसे ट्रेनिंग का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और उनका भी मानना है कि इस तरह से उत्तरांग जाने वाली सञ्जियों पूरी तरह से जैविक और स्वास्थ्यवर्धक होंगी जो उन्हें कई रोगों से निजात दिलायेंगी। अदाणी फाउंडेशन वर्तमान में 18 राज्यों में सक्रिय है, जिसमें देश भर के 2250 गाँव और कस्बे शामिल हैं। फाउंडेशन के पास प्रोफेशनल लोगों की टीम है, जो नवाचार, जन भागीदारी और सहयोग की भावना के साथ काम करती है। वार्षिक रूप से 3.2 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए अदाणी फाउंडेशन चार प्रमुख क्षेत्रों- शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, सतर आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे के विकास, पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सामाजिक पूँजी बनाने की दिशा में काम करता है।

सिंह ने पोर्टल को विकासित करने में बीआरओ के प्रयासों की

## बीरभूम हिंसा मामले में अमित शाह से मिले टीएमसी सांसद, राज्यपाल को हटाने की मांग की

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज गुरुवार को बीआरओ की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने चौथी बार भट्टा के घटनाकालीन दिन से 90 किलोमीटर दूर ही रोकने को लोकतंत्र के लिए झटका

करार दिया।

टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शाह के साथ हुई उनकी बातचीत की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि इस तरह करते हुए उनकी बातचीत की जानकारी दी।

बैठक के बाद बंदोपाध्याय ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी की वार्षिक बातचीत की मांग की और आरोप लगाया कि वह संवेधानिक प्रवाधानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, संसदीय प्रणाली उनकी बजह से खतरे में है।

नेटवर्क के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक दायित्व वाला जटिल संगठन है और सबसे बड़ी चुनौती इस एवं क्षेत्र में पूँजी निवेश थी, जिसे 2017 में केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट के विलय के बाद तो जोर देना चाहिए।

वैष्णव ने यह भी कहा कि 2014 तक पूर्वी निवेश के बजल 45,000 करोड़ रुपये था, जिसे 2017 में दोगुना कर दिया गया था और अब तक कुल 2,45,800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह बताते हुए कि किसी भी

राज्य के साथ भेदभाव का कोई योजना नहीं है, यह अस्वासन उनके पूर्ववर्ती ने भी दिया था।

अपने मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में बहस का जबाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक दायित्व वाला जटिल संगठन है और सबसे बड़ी चुनौती इस एवं क्षेत्र में पूँजी निवेश थी, जिसे

वैष्णव ने यह भी कहा कि 2009 से 2014 तक और संबंधी राज्यों की विद्युतीकरण के बारे में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इनके बाजार से इलेक्ट्रिक इंजन की ओर शिप्पिंग करने का निर्देश दिया है।

मार्गों के विद्युतीकरण के बारे में उन्होंने सदन को बताया कि कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब तक तक 80 किमी एलिवेटेड कार्गरिंडे बन चुके हैं।

अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट

ट्रेन कारिंडोर के कार्य के संबंध में उन्होंने सदन को बताया कि कार्य तीव्र गति से चल रहा है और अब अब तक 62,000 करोड़ रुपये हैं।

नए रेलवे जोन और मंडल बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर रेलवे का संचालन के लिए पूरी दुनिया रेलवे के

संचालन किया जाएगा।

वैष्णव ने यह भी कहा कि 2014 तक पूर्वी निवेश के बजल

गणेश सिंह 'विशाल'

सिंगराली, 24 मार्च । सरई तहसील अंतर्गत बासी बेरदहा गांव में पोषण संबंधी जागरूकता अभियान के तहत अदाणी फाउंडेशन द्वारा पोषण वाटिका व सभी उत्पादन पर छः दिवसीय मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का ड्रेश्य सीमित संसाधन में घेरेतु स्तर पर सालों भर ताजी सञ्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना और बाजार से सञ्जियों की खरीद पर होने वाले खर्च को कम करना है। पिछले गुरुवार से मंगलवार तक आयोजित इस कार्यक्रम में बासी बेरदहा गांव के कुल 19 महिलाएं और 12 पुरुषों को उनके खेतों में ले जाकर महिला उद्यमी बहुदेशी सहकारी समिति की श्रीमती सावित्री आर्मे और अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेप्टर की श्रीमती प्रियंका सिंह के द्वारा पोषण वाटिका के लिए एक योजना तैयार करने का आग्रह किया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त अदाणी फाउंडेशन के तरफ से सभी 31 लाभार्थी ग्रामीणों के बीच निःशुल्क पोषण वाटिका किट प्रदान किया गया जिसमें उत्तर किस्म के पालक, भिड़ी, लोबिया, केरला, लोकी, लाल साग और मिर्च की बीज थे।

अदाणी फाउंडेशन के तरफ से प्रशिक्षकों ने लाभार्थी ग्रामीणों को बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य किस्मों से अधिक होती है, जिससे कि सञ्जियों एवं फसलों में पोषक तत्व की मात्रा को सस्ते एवं सरल तरीके से बढ़ावा जा सकता है। प्रशिक्षण के उपरान्त अदाणी फाउंडेशन के तरफ से सभी 31 लाभार्थी ग्रामीणों के बीच निःशुल्क पोषण वाटिका के लिए एक योजना तैयार करने का आग्रह किया गया।

यह सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया था।

उन्होंने स्थानों की सुरक्षा और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने घरों के आगे या पीछे के छोटे हिस्से में भी कर सकते हैं। बागवानी के लिए वाटिका लगाने और सब्जी उत्पादन जैसे ट्रेनिंग का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और उनका भी मानना है कि इस तरह से उत्तरांग जाने वाली सञ्जियों पूरी तरह से जैविक और स्वास्थ्यवर्धक होंगी जो उन्हें कई रोगों से निजात दिलायेंगी। अदाणी फाउंडेशन वर्तमान में 18 राज्यों में सक्रिय है, जिसमें देश भर के 2250 गाँव और कस्बे शामिल हैं। फाउंडेशन के पास प्रोफेशनल लोगों की टीम है, जो नवाचार, जन भागीदारी और सहयोग की भावना के साथ काम करती है। वार्षिक रूप से 3.2 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए अदाणी फाउंडेशन चार प्रमुख क्षेत्रों- शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, सतर आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे के विकास, पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सामाजिक पूँजी बनाने की दिशा में काम करता है।

सिंह ने पोर्टल को विकासित करने में बीआरओ के प्रयासों की

उनके खिलाफ गुस्से में नारेबाजी करने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने अपनी घरों के आगे या पीछे के छोटे हिस्से में भी कर सकते हैं। बागवानी के लिए वाटिका लगाने और सब्जी उत्पादन जैसे ट्रेनिंग का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और उनका भी मानना है कि इस तरह से उत्तरांग जाने वाली सञ्जियों पूरी तरह से जैविक और स्वास्थ्यवर्धक होंगी जो उन्हें कई रोगों से निजात दिलायेंगी। अदाणी फाउंडेशन वर्तमान में 18 राज्यों में सक्रिय है, जिसमें देश भर के 2250 गाँव और कस्बे शामिल हैं। फाउंडेशन के पास प्रोफेशन











## सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को हस्तांतरित किए

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अयुक्त परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच कानूनी लड़ाई को 'बैटल रॉयल' करार देते हुए गुरुवार को सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया।

इस बात पर जोर देते हुए कि मामलों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सिंह के निलंबन को रद्द नहीं कर रहा है। इसने कहा कि वह सिंह के खिलाफ मामलों की जांच में केंद्रीय एजेंसी की सभी प्रकार से सहायता प्रदान करें।

अदालत ने नोट किया, 'हम यह नहीं कह रहे हैं कि अधीकारी एक विस्तलब्बोर तो उन्हें भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए।'

जरिस संजय किशन कौल

और जरिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सीबीआई को मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि प्राथमिकी में तगे आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। इसने महाराष्ट्र पुलिस को एक साथ के भीतर मामलों को सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें 5 प्राथमिकी और दो पीई शामिल हैं। इसके साथ ही इसने पुलिस को आदेश दिया कि वह सिंह के खिलाफ मामलों की जांच में उत्पन्न होने वाली परेशन करने वाली स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाया ने जोरदार तर्क दिया कि मामलों की सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य पुलिस के लिए बहुत ही मनोबल गिराने वाला होगा।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, 'तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन पुलिस आयुक्त के बीच 'बैटल रॉयल' से अस्पष्ट मंथन ने इन दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही को जन्म दिया

दिया कि इसका उद्देश्य पुलिस में लोगों का विश्वास जगाना और हासिल करना है और यह महाराष्ट्र पुलिस का प्रतिविवरण हो जाए।

पीठ ने कहा, 'उच्च स्तर पर उत्पन्न होने वाली परेशन करने वाली स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाया ने जोरदार तर्क दिया कि वह सिंह के खिलाफ मामलों की सभी प्रकार से सहायता प्रदान करें।

अदालत ने नोट किया, 'हम यह नहीं कह रहे हैं कि अधीकारी एक विस्तलब्बोर तो उन्हें भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए।'

जरिस संजय किशन कौल

पीठ पिछले साल सिंतंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर सेवा नियमों और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लंघन करने के लिए दो जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

लखनऊ, 24 मार्च (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के चुने गए 273 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम पर मुराबला दिया है।

पीठ पिछले साल सिंतंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर सेवा नियमों और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लंघन करने के लिए दो जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

राजनीतिक अस्थिरता का माहाल 2014 तक चला। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने 2014, 2017 और 2019 में मिली जीत का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे 2014 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को विश्वास हुआ कि उनकी पार्टी यूपी में 300 पार जा सकती है।

अमित शाह ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की सरकारों ने योगी जी के नेतृत्व में पूरा करना है। अमित शाह ने कहा, "आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि यूपी विधानसभा का नया इतिहास लिखने का क्षण हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भाजपा अकेली पार्टी है जिसने दोनों बार दो तिहाई समर्थन दिया है। यूपी की स्थापना से अब तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हमारे लिए आनंद का विषय है कि योगी जी को दूसरी बार जनता ने चुना है।"

अमित शाह ने कहा कि 2017 में जब योगी ने सत्ता संभाली तो उनके सामने दोर सारी चुनौतियाँ थीं, विधायक अर्थत्र था, छिन्न-भिन्न प्रशासनिक दंच था। पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था, राजनीति का अपराधीकरण हो गया था, कानून-व्यवस्था का कोई तौर पर जमीन पर नहीं पहुंचा।

शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास की नींव डालने का काम जो 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल यूपी को खोंचे हुए गौरव को जनता की आशा को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि "यूपी कई सालों से परानग एक अर्थव्यवस्था का बनाने का उद्देश्य था। यूपी को दूसरी बार जनता ने चुना है।"

अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समर्थन में बुरी तरह विफल रही है। यूपी की विधानसभा का नया इतिहास लिखने का क्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म द एक विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है। उन्होंने कहा कि यूपी की विधायक अधिकारी को दूसरी बार जनता ने चुना है।

## द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर करें अपलोड, टैक्स फ्री पर बोले केजरीवाल

नई दिल्ली, 24 मार्च (एजेन्सी)। द कश्मीर फाइल्स के नरसंहार के 32 साल बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लाई गई। कश्मीरी पंडितों के एक सांगठन ने 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडितों की कथित समूहिक हव्याओं और नरसंहार की केंद्रीय जांच एंजी एवं नरसंहार की जांच करनी चाहिए, न उनका विश्वास नहीं है, भले ही वह उसी का नेतृत्व कर रहे हैं।

यह याचिका रूपस इन कश्मीरी पंडितों के बारे में दायर की है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर रोपे करोड़ों पैसे दिये गए हैं। दिल्ली विधानसभा म